

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

विभाग: वित्त (अनुभाग-8)

देहरादून :: दिनांक:: 31 अक्टूबर, 2013

विषय: राज्य सरकार के कार्मिकों को वाहनों की खरीद पर पड़ने वाले कर(वैट) के भार से मुक्ति दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कार्मिकों को दुपहिया वाहन यथा मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड एवं चौपहिया वाहन के निजी उपयोग हेतु क्रय पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय कर की धनराशि की प्रतिपूर्ति, निम्न शर्तों के अधीन की जाएगी :-

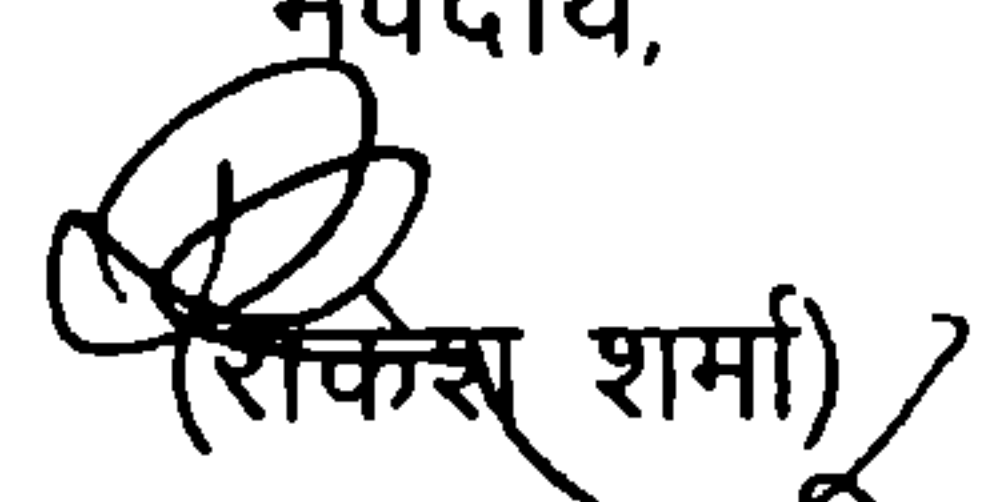
- (1) दुपहिया वाहन का विक्रय मूल्य रुपये साठ हजार(वैट को छोड़कर) से अधिक नहीं होगा;
- (2) चौपहिया वाहन का विक्रय मूल्य रुपये पाँच लाख(वैट को छोड़कर) से अधिक नहीं होगा;
- (3) किसी भी सेवारत कार्मिक को सेवाकाल में उपर्युक्त सुविधा एक वाहन(चाहे वह दुपहिया हो अथवा चौपहिया) के लिए और एक ही बार अनुमन्य होगी। क्रय किया गया ऐसा वाहन 5 वर्ष से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित अथवा विक्रय नहीं किया जायेगा;
- (4) यदि कार्मिक के परिवार में किसी सदस्य के पास पहले से ही कोई वाहन उपलब्ध है तो यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी किन्तु परिवार में यदि कोई वाहन है तो उसका रिप्लेसमेन्ट अनुमन्य होगा;
- (5) उक्त "प्रतिपूर्ति", संबंधित कार्मिक के विभागाध्यक्ष के द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्ररूप संलग्न) के आधार पर कोषागार द्वारा, कार्मिक के खाते में भुगतान के आधार पर की जायेगी;
- (6) "प्रमाण पत्र" जारी करने से पूर्व, विभागाध्यक्ष द्वारा वाहन के क्रय का सत्यापन, कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए गए वाहन के बीजक, वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा वाहन के insurance के कागजातों से किया जायेगा;

(7) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा, सेवारत कार्मिकों के सेवा अभिलेखों में उपर्युक्त "प्रमाण पत्र" जारी करने तथा वाहन के क्रय संबंधी प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाएगा;

(8) एक वित्तीय वर्ष में, अधिकतम 1000 दुपहियां वाहनों एवं अधिकतम 500 चौपहियां वाहनों हेतु प्रतिपूर्ति, प्रथम आगत प्रथम पावत(first come first serve) के आधार पर की जाएगी तथा उक्त सुविधा सेवारत कार्मिक को सेवाकाल में प्रत्येक दशा में मात्र एक ही वाहन हेतु (चाहे वह दुपहियां हो अथवा चौपहियां) एक बार के लिये ही अनुमन्य होगी।

(9) उपर्युक्त "प्रतिपूर्ति" हेतु, अनुदान सं० 7 के अन्तर्गत, बजट प्राविधान किया जाएगा। निदेशक कोषागार "प्रतिपूर्ति" हेतु नियंत्रक अधिकारी होंगे तथा उनके द्वारा इस हेतु तैयार की गयी software utility के माध्यम से, employee code, क्लेम प्राप्त होने की तिथि, वाहन के बीजक का विवरण, कार्मिक के खाते में प्रतिपूर्ति संबंधी भुगतान की तिथि आदि का विवरण रखते हुए शर्त सं० 5 एवं 8 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा त्रैमासिक रूप से सम्बंधित बीजकों की सूचना आयुक्त कर को दी जाएगी।

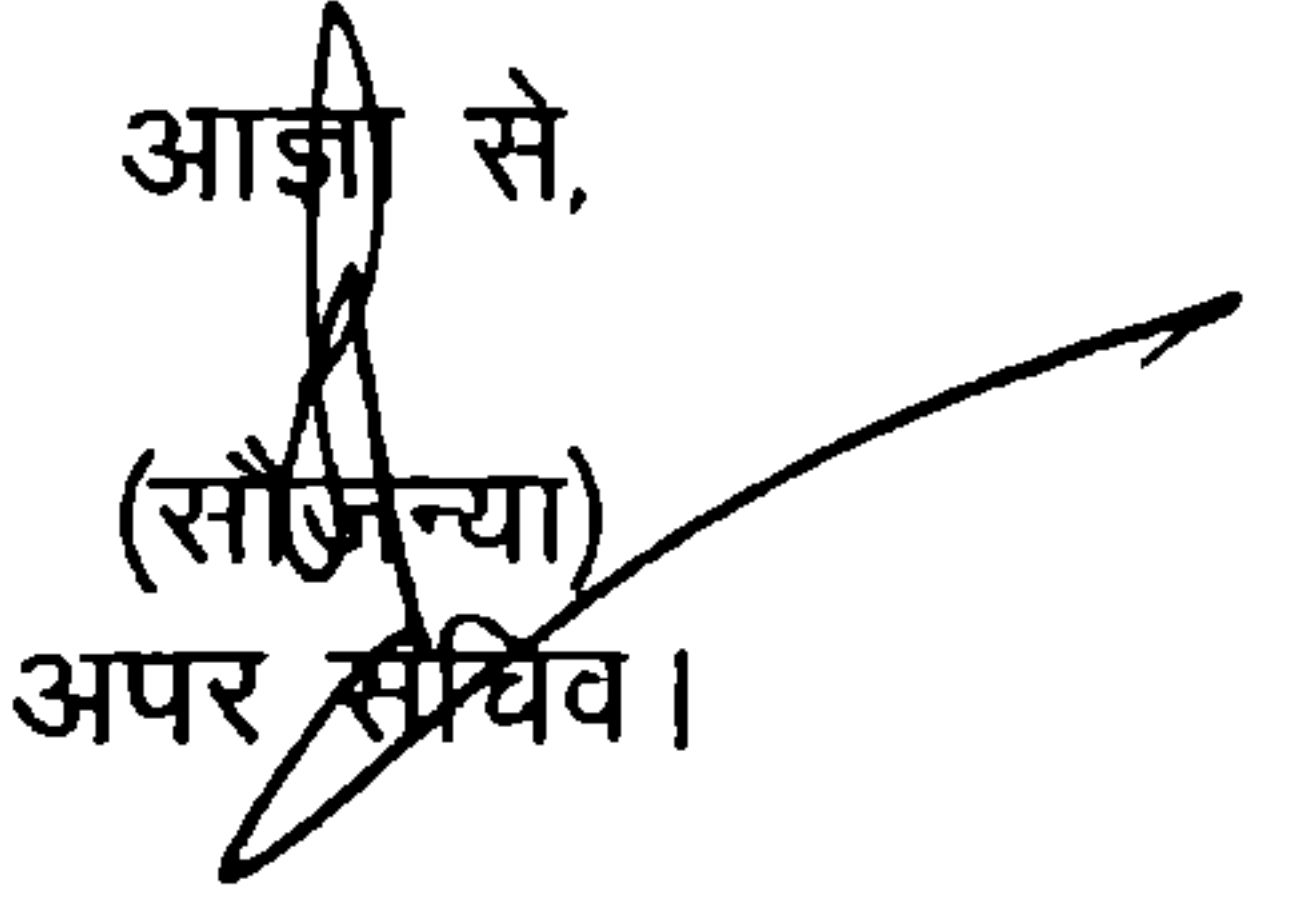
संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(रकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृ०प०सं० 1235 / 2013 / 14(120) / XXVII(8) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा० वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 7- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(सौजन्या)
अपर सचिव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिक द्वारा निम्न वाहन क्रय किया गया है जिस पर अदा किए गए कर (वैट) के भार की निम्न राशि की प्रतिपूर्ति शासनादेश सं०.....दिनांक..... के अन्तर्गत किए जाने योग्य है :-

1. कार्मिक का employee code
2. कार्मिक का नाम व पदनाम
3. क्रय किए गए वाहन की पंजीयन संख्या
4. वाहन का प्रकार(दुपहिया अथवा चौपहिया)
5. Insurance कम्पनी का नाम व पता
6. वाहन के विक्रेता का नाम व पता
7. विक्रेता का टिन संख्या
8. बिक्री का बीजक संख्या एवं दिनांक
9. वाहन का विक्रय मूल्य(वैट को छोड़कर)
10. बीजक में वसूला गया कर(वैट)
11. शासनादेश के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य राशि(अंकों में)
12. शासनादेश के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य राशि (शब्दों में)

हस्ताक्षर,
विभागाध्यक्ष